

PM Modi Embarks on Five-Nation Tour to Strengthen Global South Ties & Attend BRICS Summit



Category: International Relations

Such a tactical approach enhances the diplomatic, economic, and cultural interaction of India with countries of the Global South and the position of India in the BRICS as the voice of developing countries. The visit features attending the BRICS Summit in Brazil, which advances a multipolar system of world order. PM Modi became the recipient of the highest civilian awards in Ghana and Trinidad and Tobago. The main areas of interests here entail vaccine diplomacy, economic partnerships, capacity building, and South-South cooperation. The tour revitalizes India as a world power in the ambitions of its world leadership, especially the reforms of international governing organisations such as BRICS.

Context

- PM Modi started a diplomatic visit to five countries, including Ghana, Trinidad & Tobago, Brazil, Argentina, and Namibia, as part of enhancing relations with the Global South.

BRICS Summit Convergence



Key Highlights

Themes

- Enhancement of South-South cooperation
- BRICS in the promotion of multipolar world order
- Advancement of inequality when it comes to the administering of the vaccine, digital infrastructure of the people, and green partnerships
- Increasing cultural, trade and development ties with Africa, Latin America, and the Caribbean

Key Destinations & Highlights

Country	Key Engagements
Ghana	Meeting with President Mahama; highest honour conferred; vaccine production talks.
Trinidad & Tobago	Order of the Republic awarded; focus on cultural heritage and Caribbean ties.
Brazil	Attending BRICS Summit in Rio; bilateral talks; multilateral diplomacy.



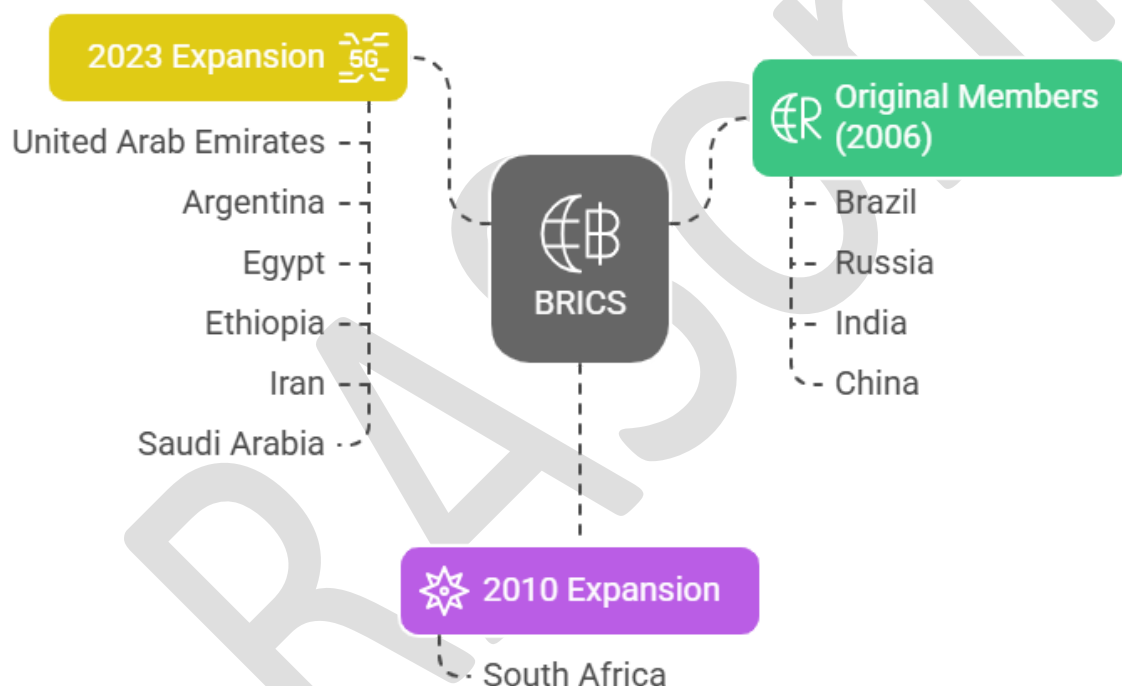
Argentina	Strengthening strategic cooperation, trade, and regional connectivity.
Namibia	Parliament address; cooperation in energy, technology, and development.

About BRICS

What is BRICS?

- A group of 5 eminent emerging economies:
 - Brazil, Russia, India, China, South Africa
- BRICS 2025 Summit will be organized in Rio de Janeiro, Brazil, on July 6-7, 2025 with the agenda that will be based on global governance reforms and improved cooperation among the countries of the Global South.
- **Timeline:**

BRICS Expansion and Membership



- Incorporated: 2006 as BRIC
- New members added: 2010 including South Africa
- During the Johannesburg Summit 2023, the BRICS embarked upon welcoming six new countries as its members:
 - The United Arab Emirates, Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran and Saudi Arabia.
- **Goals:**
 - Renew world organization (UN, IMF, WTO)
 - Embrace sustainable development, economic growth
 - Encourage a multi-polar world environment

Key BRICS Institutions

Institution	Function
New Development Bank (NDB)	Funds infrastructure & sustainable projects in BRICS & Global South
Contingent Reserve Arrangement	Currency support during balance-of-payment crises
Annual BRICS Summit	Platform to coordinate on trade, health, development, climate change, etc.

India's Role in BRICS

Pillar	India's Approach
Strategic Leadership	Vocal for Global South priorities and multilateralism
UN Reform Advocacy	Pushes for UNSC permanent membership & democratic global institutions
Economic Engagement	Promotes digital economy, fintech, energy security, and climate justice
Health Diplomacy	Led BRICS Vaccine R&D Centre; championed equitable access during COVID-19
Balance with China	Uses BRICS as a neutral ground to engage diplomatically amid border tensions

BRICS problems

- Geopolitical tensions such as the India-China tensions etc.
- The imbalanced economy where China is leader in trade and investment
- Inconsistency in policies among the various members
- Limits of institutions and obstructions of implementation

Indian vision of BRICS

- Global system based on multi polarity and inclusivity
- Cooperation in digital infrastructure, artificial intelligence and green energy
- Fair climate and equitable growth of all the BRICS countries and the Global South countries

Conclusion

The five-nation visit that was done by PM Modi is a strategic diplomatic effort focusing on the Indian leadership in Global South as well as active participation in BRICS. It goes in line with the multipolar vision of India, the economic diplomacy of the country and interests in reforming the global governance structures. The visit is an important milestone in strengthening Indian capability as a global and ethical leader in the changing international order.



प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक दक्षिण संबंधों को मजबूत करने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पांच देशों की यात्रा पर रवाना हुए



PM MODI BEGINS BRICS TOUR TO BOOST GLOBAL SOUTH

इस तरह का सामरिक दृष्टिकोण वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ भारत के कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ाता है तथा विकासशील देशों की आवाज के रूप में ब्रिक्स में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। इस यात्रा में ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेना शामिल है, जो विश्व व्यवस्था की बहुध्रुवीय प्रणाली को आगे बढ़ाता है। पीएम मोदी घाना और त्रिनिदाद और टोबैगो में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले बने। यहां रुचि के मुख्य क्षेत्र वैक्सीन कूटनीति, आर्थिक साझेदारी, क्षमता निर्माण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग हैं। यह यात्रा भारत को अपने विश्व नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं, विशेष रूप से ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय शासी संगठनों के सुधारों में एक विश्व शक्ति के रूप में पुनर्जीवित करती है।

प्रसंग

- प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक दक्षिण के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, ब्राजील, अर्जेंटीना और नामीबिया सहित पांच देशों की राजनयिक यात्रा शुरू की।

BRICS Summit Convergence



मुख्य बातें

विषय-वस्तु

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग में वृद्धि
- बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने में ब्रिक्स
- जब वैक्सीन लगाने, लोगों के डिजिटल बुनियादी ढांचे और हरित साझेदारी की बात आती है तो असमानता की प्रगति
- अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई देशों के साथ सांस्कृतिक, व्यापारिक और विकास संबंधों को बढ़ाना

प्रमुख गंतव्य एवं मुख्य आकर्षण

देश	प्रमुख कार्य
घाना	राष्ट्रपति महामा से मुलाकात; सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया; वैक्सीन उत्पादन पर बातचीत।
ट्रिनिडाड और टोबैगो	ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित; सांस्कृतिक विरासत और कैरेबियाई संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
ब्राज़िल	उपस्थित होना ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो में; द्विपक्षीय वार्ता; बहुपक्षीय कूटनीति।
अर्जेंटीना	रणनीतिक सहयोग, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना।



<https://t.me/+9dLgyy8BipQ3YjB>



HYPERLINK
"https://rasonly.com" <https://rasonly.com>

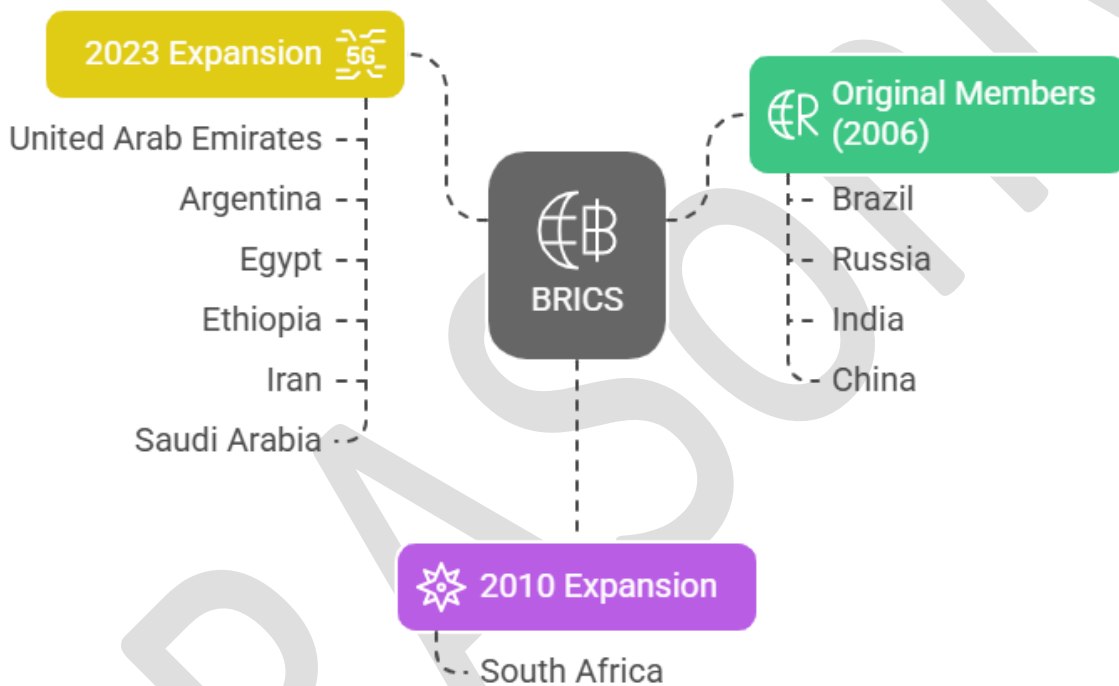
नामिबिया	संसद में संबोधन; ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और विकास में सहयोग।
----------	--

ब्रिक्स के बारे में

ब्रिक्स क्या है?

- 5 प्रतिष्ठित उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह:
 - ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका
- ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन 6-7 जुलाई, 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा, जिसका एजेंडा वैश्विक शासन सुधार और वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच बेहतर सहयोग पर आधारित होगा।
- समयरेखा:

BRICS Expansion and Membership



- निगमित: 2006 में BRIC के रूप में
- नये सदस्य जोड़े गए: 2010 में दक्षिण अफ्रीका सहित
- जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान, ब्रिक्स ने अपने सदस्य के रूप में छह नए देशों का स्वागत किया:
- संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरब।
- लक्ष्य:
 - नवीनीकृत विश्व संगठन (यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ)
 - सतत विकास, आर्थिक वृद्धि को अपनाएं
 - बहुधुवीय विश्व पर्यावरण को प्रोत्साहित करें

प्रमुख ब्रिक्स संस्थाएँ



<https://t.me/+9dLgyy8BipQ3YjB>



HYPERLINK
["https://rasonly.com"](https://rasonly.com)
<https://rasonly.com>

संस्था	समारोह
न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)	ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण में बुनियादी ढांचे और टिकाऊ परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है
आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था	भुगतान संतुलन संकट के दौरान मुद्रा समर्थन
वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन	व्यापार, स्वास्थ्य, विकास, जलवायु परिवर्तन आदि पर समन्वय हेतु मंच।

ब्रिक्स में भारत की भूमिका

गोलियाँ	भारत का दृष्टिकोण
रणनीतिक नेतृत्व	वैश्विक दक्षिण प्राथमिकताओं और बहुपक्षवाद के पक्ष में मुखर
संयुक्त राष्ट्र सुधार वकालत	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और लोकतांत्रिक वैश्विक संस्थाओं के लिए प्रयास
आर्थिक जुड़ाव	डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु न्याय को बढ़ावा देता है
स्वास्थ्य कूटनीति	ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र का नेतृत्व किया; कोविड-19 के दौरान न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा दिया
चीन के साथ संतुलन	सीमा पर तनाव के बीच कूटनीतिक रूप से बातचीत करने के लिए ब्रिक्स को तटस्थ आधार के रूप में उपयोग करना

ब्रिक्स समस्याएं

- भू-राजनीतिक तनाव जैसे भारत-चीन तनाव आदि।
- असंतुलित अर्थव्यवस्था जहां चीन व्यापार और निवेश में अग्रणी है
- विभिन्न सदस्यों के बीच नीतियों में असंगति
- संस्थाओं की सीमाएं और कार्यान्वयन में बाधाएं

ब्रिक्स के प्रति भारतीय दृष्टिकोण

- बहुध्रुवीयता और समावेशिता पर आधारित वैश्विक प्रणाली
- डिजिटल अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हरित ऊर्जा में सहयोग
- सभी ब्रिक्स देशों और वैश्विक दक्षिण देशों के लिए उचित जलवायु और समान विकास

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई पांच देशों की यात्रा वैश्विक दक्षिण में भारतीय नेतृत्व के साथ-साथ ब्रिक्स में सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित एक रणनीतिक कूटनीतिक प्रयास है। यह भारत के बहुध्रुवीय दृष्टिकोण, देश की आर्थिक कूटनीति और वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार के हितों के अनुरूप है। यह यात्रा बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक वैश्विक और नैतिक नेता के रूप में भारतीय क्षमता को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।



Phone Tapping Not Permissible for Crime Detection: Madras High Court



Category: National, Governance

The Madras High court decreed that any phone tapping to identify crimes, even corruption constitutes violation of fundamental right to privacy under Article 21 save and except with express permission in the Indian Telegraph Act, 1885. It was a case, which dealt with a situation concerning interception of phones in an investigation into bribery in the year 2011. Justice N. Anand Venkatesh reiterated that even in probing serious crimes, constitutional rights cannot be short changed. The Puttaswamy judgment was cited and the interception was quashed by the court with the solidification of the view that covert surveillance can only be used in cases of public emergency or public safety and not on a routine tip.

Context

- Madras High Court stated that the privacy is breached in the case of hidden phone tapping as a method to detect crime unless reasonably provided by and under the law.
- The decision enhances constitutional protection against state scrutiny.

Key Highlights

Legal Context

- Telegraph Act 1885, 5 (2):
 - Allows only interception when:
 - National emergency
 - Out of interest of the safety of the people
 - Telegraph Rules 419A: Gives the formal procedure protections of phone tapping



<https://t.me/+9dLgyy8BipQ3YjB>



HYPERLINK
["https://rasonly.com"](https://rasonly.com)htt
 ps://rasonly.com

Phone tapping legality

Pros

- Crime prevention
- National security

Cons

- Privacy violation
- Misuse potential
- Legal challenges

Case Background

- **Petitioner:** P. Kishore, Chennai-based businessman
- Year: 2011
- Allegation: 50 lakhs bribe in colab with IRS officer Andasu Ravinder
- Phone Tapping is Legal: It is sanctioned by the MHA, in the pretext of the safety of the people

Court's Ruling

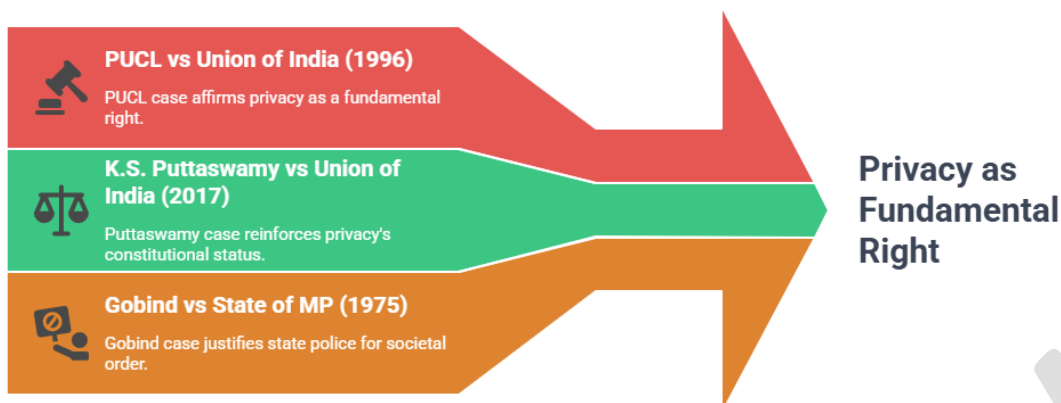
- Tapping on phones was against constitution:
 - Not justified under Section 5(2)
 - Did not have transparent criteria on emergency in front of the people
- Provisions of Article 21 Right to privacy violated
- Eavesdropping has to be according to procedure laid down in law
- Street cancelled the authorisation granted to MHA and forbade the usage of intercepted calls in the evidence part

Key Legal Precedents Cited

- PUCL vs Union of India (1996)
- K.S. Puttaswamy. The case vs Union of India (2017)
- **Gobind vs State of MP (1975)**
 - All affirm **privacy as intrinsic to personal liberty under Article 21**



Legal Pillars of Privacy



Broader Implications

- Limits government surveillance excesses by the executive branch
- Strengthens the judicial process and constitutional responsibility
- Enhances privacy law back up according to the Puttaswamy judgment
- There has been a cry on striking a balance between national security and individual freedom

Conclusion

The judgment confirms the fact that privacy is a divine fundamental right and the investigative bodies should have legality and constitutional limits. It provides solid legal protection against unseeable monitoring and creates an example of respecting citizen freedoms in the online age.

अपराध का पता लगाने के लिए फोन टैपिंग की अनुमति नहीं: मद्रास उच्च न्यायालय



PHONE TAPPING CAN'T BE USED FOR CRIME DETECTION: HC

मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपराधों, यहां तक कि भ्रष्टाचार की पहचान करने के लिए किसी भी फोन टैपिंग को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 में स्पष्ट अनुमति के बिना अनुच्छेद 21 के तहत निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। यह एक ऐसा मामला था, जो वर्ष 2011 में रिश्वतखोरी की जांच में फोन इंटरसेप्शन से संबंधित स्थिति से निपटता था। न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने दोहराया कि गंभीर अपराधों की जांच में भी संवैधानिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। पुट्टस्वामी फैसले का हवाला दिया गया और अदालत ने इस दृष्टिकोण को पुष्टा करते हुए इंटरसेप्शन को रद्द कर दिया कि गुप्त निगरानी का इस्तेमाल केवल सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में किया जा सकता है, न कि नियमित सूचना पर।

प्रसंग

- मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि अपराध का पता लगाने की विधि के रूप में गुप्त फोन टैपिंग के मामले में गोपनीयता का उल्लंघन होता है, जब तक कि कानून द्वारा और उसके तहत उचित प्रावधान न किया गया हो।
- यह निर्णय राज्य की जांच के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण को बढ़ाता है।

मुख्य बातें

कानूनी संदर्भ

- टेलीग्राफ अधिनियम 1885, 5 (2):
 - केवल तभी अवरोधन की अनुमति देता है जब:
 - राष्ट्रीय आपातकाल
 - लोगों की सुरक्षा के हित में
 - टेलीग्राफ नियम 419A: फोन टैपिंग की औपचारिक प्रक्रिया सुरक्षा प्रदान करता है

Phone tapping legality

Pros	Cons
○ Crime prevention ○ National security	○ Privacy violation ○ Misuse potential ○ Legal challenges

मामले की पृष्ठभूमि

- याचिकाकर्ता: पी. किशोर, चेन्नई स्थित व्यवसायी
- वर्ष: 2011
- आरोप: आईआरएस अधिकारी अंदासु रविंदर के साथ कोलाब में 50 लाख की रिश्वत
- फ़ोन टैपिंग कानूनी है: लोगों की सुरक्षा के नाम पर गृह मंत्रालय द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है

न्यायालय का निर्णय

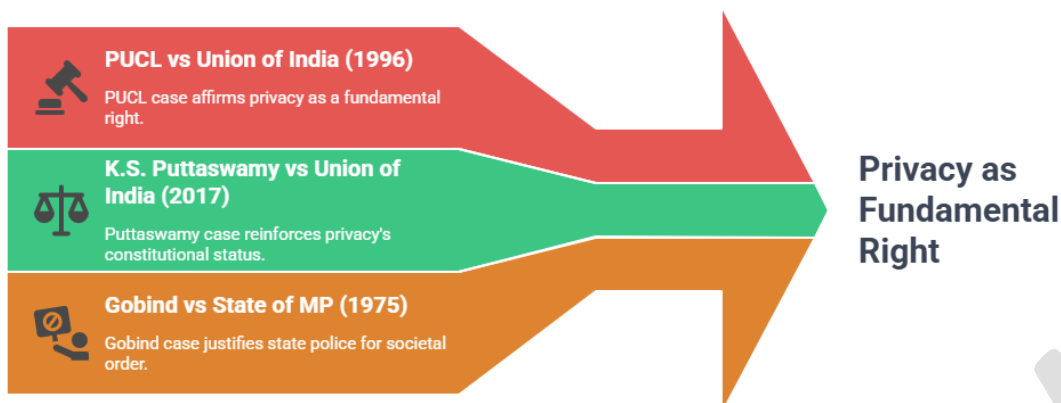
- फोन टैपिंग संविधान के विरुद्ध थी:
 - धारा 5(2) के अंतर्गत उचित नहीं
 - लोगों के सामने आपातकाल पर पारदर्शी मापदंड नहीं रखे गए
- अनुच्छेद 21 के प्रावधान निजता के अधिकार का उल्लंघन
- गुप्त रूप से सुनने का काम कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए
- स्ट्रीट ने गृह मंत्रालय को दिए गए प्राधिकरण को रद्द कर दिया और साक्ष्य भाग में इंटरसेप्टेड कॉल के उपयोग पर रोक लगा दी

उद्धृत प्रमुख कानूनी मिसालें

- पीयूसीएल बनाम भारत संघ (1996)
- के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)
- गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1975)
 - सभी पुष्टि करते हैं अनुच्छेद 21 के तहत निजता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना गया



Legal Pillars of Privacy



व्यापक निहितार्थ

- कार्यकारी शाखा द्वारा सरकारी निगरानी की ज्यादतियों को सीमित करता है
- न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक जिम्मेदारी को मजबूत करता है
- पुट्टस्वामी निर्णय के अनुसार गोपनीयता कानून को मजबूत किया गया
- राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की मांग उठ रही है

निष्कर्ष

यह निर्णय इस तथ्य की पुष्टि करता है कि निजता एक दैवीय मौलिक अधिकार है और जांच निकायों के पास वैधानिकता और संवैधानिक सीमाएं होनी चाहिए। यह अदृश्य निगरानी के खिलाफ ठोस कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और ऑनलाइन युग में नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

Rajasthan

Pandit Deendayal Upadhyay Garibi Mukht Gram Yojana: A Revolutionary Step Towards Rural Poverty Eradication in Rajasthan

Sector: Rural Development and Social Welfare

Subject: Government Schemes – Poverty Alleviation & Economic Empowerment in Rajasthan

Key Points of the News:

- The Rajasthan government launched '**Pandit Deendayal Upadhyay Garibi Mukht Gram Yojana**' to empower BPL rural families and uplift them above the poverty line.
- First phase** covers **5000 villages**, targeting **30,631 BPL families**.



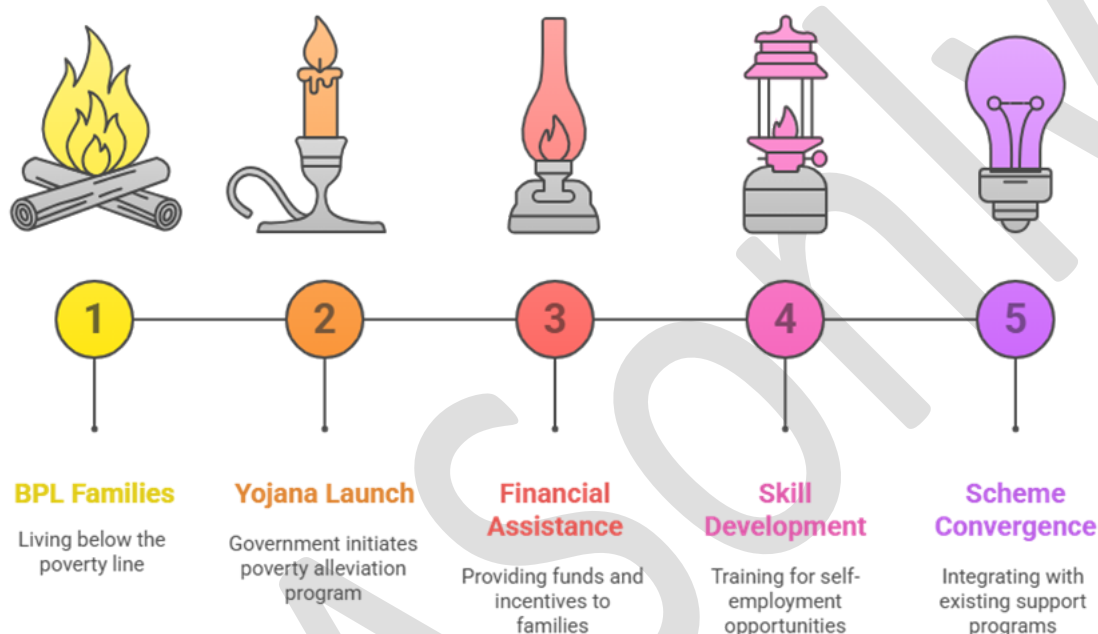
<https://t.me/+9dLgyy8BipQ3YjB>



HYPERLINK
"<https://rasonly.com>"
<https://rasonly.com>

- **₹300 crore** allocated for implementation.
- Families already above the poverty line will be given **₹21,000 incentive** and '**Aatmanirbhar Parivar Card**'.
- **61,442 applications** received from families needing support.
- Aid up to **₹1 lakh** for self-employment; **₹15,000 working capital** to SHG-linked women.
- **Tri-monthly ranking** and **district awards**: ₹50 lakh, ₹35 lakh, ₹25 lakh.
- **Second phase** covers 5002 more villages; **22,872 family surveys completed**.
- Web portal integrated with **BPL Census 2002** for validation.
- Focus on **skill development**, **financial inclusion**, and **convergence with other schemes**.

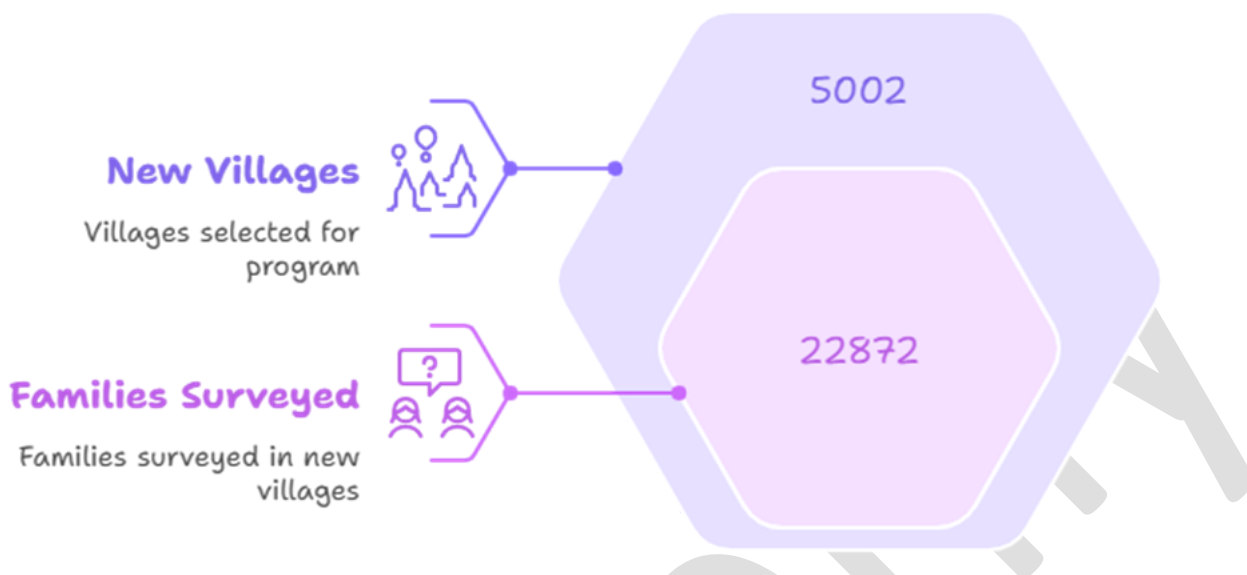
Empowering BPL Families in Rajasthan



Detailed Explanation for RAS Mains:

- **Objective:**
 - Poverty alleviation in rural Rajasthan.
 - Making villages 'Poverty-Free' through convergence of schemes and targeted assistance.
- **Incentive for Self-Reliance:**
 - ₹21,000 given to families who moved out of poverty line through their own efforts.
 - Promotes dignity-based recognition and motivation.

Rajasthan Poverty Alleviation Program: Village Coverage



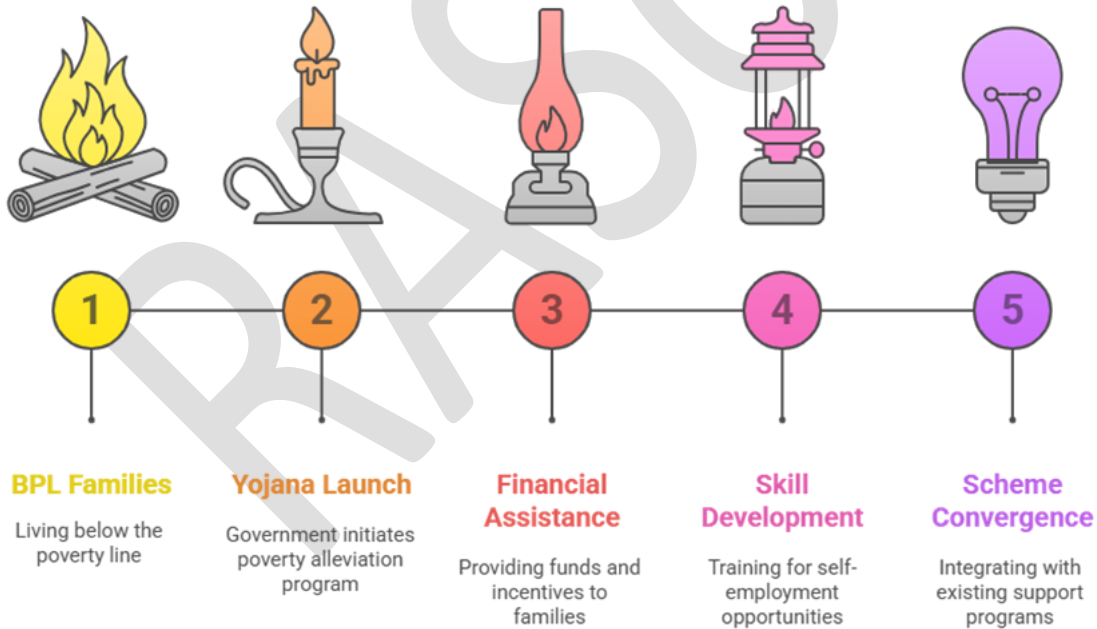
- **Beneficiary Identification:**
 - Based on **BPL Census 2002**.
 - **Physical survey** already completed in the first phase.
 - Verified data uploaded on a government portal for transparency and tracking.
- **Scope of Financial Assistance:**
 - **₹1 lakh maximum** for income-generating activities (like small business, animal husbandry, agriculture-based work).
 - For women in SHGs, **₹15,000** for working capital to boost entrepreneurship.
- **Application Process:**
 - Open to families still in poverty.
 - Encouraged to apply and get linked with state schemes for skill and livelihood.
- **Special Focus on District Performance:**
 - Competitive approach with **rewards to districts** based on their effective implementation.
 - Rankings every quarter to maintain momentum.
- **Second Phase Rollout:**
 - Covers **5002 new villages**; survey of 22,872 families done.
 - More families to be linked with support and schemes.
- **Scheme Impact and Vision:**
 - Moves beyond welfare to **empowerment and sustainability**.
 - Enables convergence of poverty relief, skill development, and financial inclusion.
 - In alignment with **Antyodaya Philosophy** – upliftment of the last person in society.

राजस्थान में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना': ग्रामीण विकास की नई क्रांति

मुख्य बिंदु:

- राजस्थान सरकार ने बीपीएल ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' की शुरुआत की।
- प्रथम चरण में 5000 गांव और 30,631 बीपीएल परिवारों का चयन।
- योजना हेतु ₹300 करोड़ की राशि स्वीकृत।
- गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके परिवारों को ₹21,000 प्रोत्साहन राशि और 'आत्मनिर्भर परिवार कार्ड' प्रदान।
- 61,442 परिवारों ने सहायता हेतु आवेदन किया।
- स्वरोजगार हेतु ₹1 लाख, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ₹15,000 तक कार्यशील पूंजी।
- जिलों को त्रैमासिक प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार: प्रथम ₹50 लाख, द्वितीय ₹35 लाख, तृतीय ₹25 लाख।
- दूसरे चरण में 5002 गांव शामिल; 22,872 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा।
- योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि समाज में समावेशन और सम्मानपूर्ण आत्मनिर्भरता है।

Empowering BPL Families in Rajasthan



RAS मुख्य परीक्षा हेतु संक्षिप्त विश्लेषण:



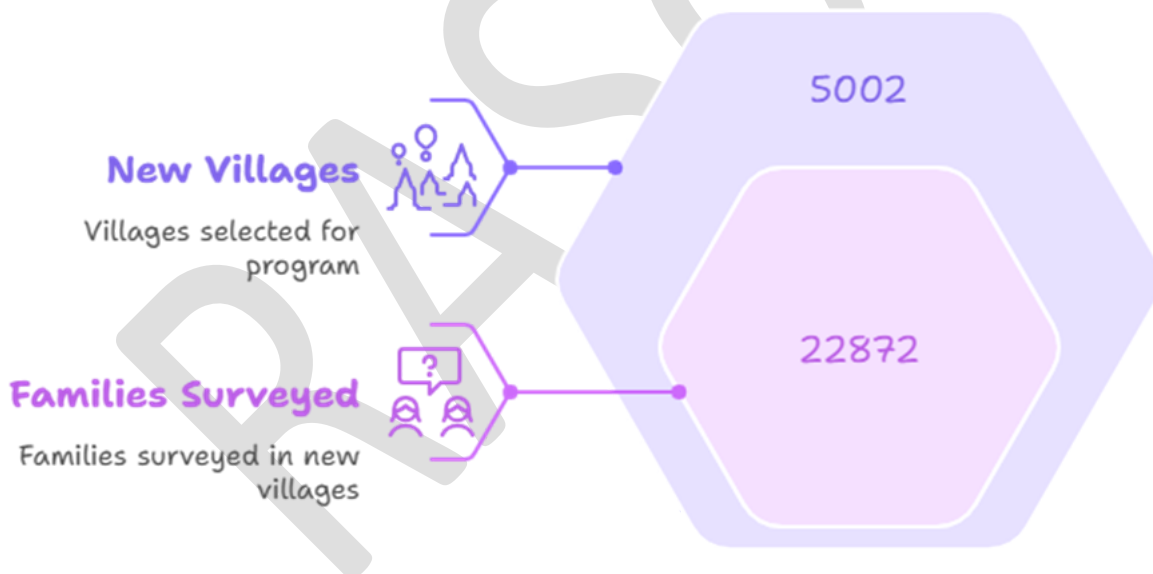
<https://t.me/+9dLgyv8BipQ3YjB>



HYPERLINK
["https://rasonly.com"](https://rasonly.com)
<https://rasonly.com>

- **योजना का उद्देश्य:**
 - ग्रामीण राजस्थान को गरीबी से मुक्त करना।
 - आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
- **प्रोत्साहन राशि की विशेषता:**
 - अपने प्रयास से गरीबी से ऊपर उठे परिवारों को ₹21,000।
 - आत्मसम्मान को बढ़ावा देने की पहल।
- **लाभार्थी चयन प्रक्रिया:**
 - बीपीएल जनगणना 2002 के आधार पर चयन।
 - सर्वेक्षण के बाद पोर्टल पर डेटा अपलोड।
- **वित्तीय सहायता का दायरा:**
 - स्वरोजगार हेतु ₹1 लाख तक।
 - महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹15,000 कार्यशील पूंजी।

Rajasthan Poverty Alleviation Program: Village Coverage



- **अर्जियों की स्थिति:**
 - 61,442 नए आवेदन - जिन्हें राज्य की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
- **जिला प्रोत्साहन पुरस्कार:**
 - कार्य निष्पादन के आधार पर तीन जिलों को वित्तीय पुरस्कार।

- **द्वितीय चरण की तैयारी:**
 - 5002 नए गांव चयनित।
 - 22,872 परिवारों का सर्वे पूर्ण।
- **सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन:**
 - अन्त्योदय दर्शन की भावना के अनुरूप योजना।
 - राज्य में स्थायी ग्रामीण विकास की दिशा में क्रांतिकारी प्रयास।

MCQs in English and Hindi

Subject: Government Schemes

Topic: Rural Development – Rajasthan

Question:

Under the Pandit Deendayal Upadhyay Garibi Mukta Gram Yojana, what is the maximum financial assistance provided to BPL families for self-employment activities?

1. ₹50,000
2. ₹75,000
3. ₹1,00,000
4. ₹1,50,000

Answer: 3. ₹1,00,000

Explanation: The scheme provides up to ₹1 lakh assistance for self-employment and livelihood-related activities to BPL families.

प्रश्न:

पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार हेतु अधिकतम कितनी सहायता राशि दी जाती है?

1. ₹50,000
2. ₹75,000
3. ₹1,00,000
4. ₹1,50,000

उत्तर: 3. ₹1,00,000

व्याख्या: यह योजना बीपीएल परिवारों को आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम ₹1 लाख तक सहायता देती है।

Subject: Social Welfare

Topic: Poverty Eradication Schemes – Rajasthan

Question:

What is the incentive amount provided to families who have moved above the poverty line through their own efforts under the new Rajasthan rural poverty scheme?



1. ₹10,000
2. ₹15,000
3. ₹21,000
4. ₹25,000

Answer: 3. ₹21,000

Explanation: The scheme rewards such families with ₹21,000 along with an 'Aatmanirbhar Parivar Card' as a recognition of their self-reliance.

प्रश्न:

राजस्थान की नई ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना में, अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर उठे परिवारों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है?

1. ₹10,000
2. ₹15,000
3. ₹21,000
4. ₹25,000

उत्तर: 3. ₹21,000

व्याख्या: ऐसे परिवारों को आत्मनिर्भरता के प्रतीक रूप में ₹21,000 की राशि एवं 'आत्मनिर्भर परिवार कार्ड' प्रदान किया जा रहा है।

Rajasthan Shines in National Ice Skating Championship

Sector: Sports

Subject: Winter Sports – Ice Skating | Rajasthan's National Performance

- Rajasthan's 28-member team participated in the 20th National Ice Skating Championship held in Dehradun.
- The team performed excellently, earning recognition for their skill and coordination.
- The leadership of the team was under Sanjeev Kumar, Rachna Pradhan, and Anil Kumar.
- Jagraj Singh, Secretary General of the Ice Skating Association of India, praised all participants for their commendable performances.



Top Contributors to Rajasthan's Ice Skating Team



Sanjeev Kumar

Sanjeev Kumar led the Rajasthan ice skating team with discipline and strategy.



Rachna Pradhan

Rachna Pradhan contributed to team morale and competitive spirit.



Anil Kumar

Anil Kumar helped guide the team, enhancing team discipline and strategy.

Detailed Explanation (For RAS Mains):

- **Event Significance:** The 20th National Ice Skating Championship is a premier winter sports event conducted annually in India to promote ice skating as a competitive sport.
- **Rajasthan's Participation:** Despite being a desert state with limited natural conditions for winter sports, Rajasthan's 28-member team showcased strong preparation and competitive spirit.
- **Team Leadership:**
 - **Sanjeev Kumar, Rachna Pradhan, and Anil Kumar** guided the team, likely contributing to team discipline, strategy, and morale.
- **Recognition by National Body:** Jagraj Singh, Secretary General of the Ice Skating Association of India, acknowledged Rajasthan's team's dedication and achievements, signaling national recognition and possible future support.
- **Promotion of Non-traditional Sports:** Rajasthan's performance reflects the growing diversification of sports training in the state, including niche areas like winter sports.
- **Future Implications:**
 - Encouragement for youth to explore less popular sports.
 - Potential for government/private support to develop artificial rinks or training centers.
 - Inclusion of winter sports in state-level games and policies.

हिम क्रीड़ा में राजस्थान की उत्कृष्टता

- देहरादून में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की 28 सदस्यीय टीम ने भाग लिया।



- टीम ने शानदार प्रदर्शन कर राज्य को गौरवान्वित किया।
- टीम का नेतृत्व संजीव कुमार, रचना प्रधान और अनिल कुमार ने किया।
- आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुख्य सचिव जगराज सिंह ने राजस्थान के प्रदर्शन की सराहना की।

Top Contributors to Rajasthan's Ice Skating Team



Sanjeev Kumar

Sanjeev Kumar led the Rajasthan ice skating team with discipline and strategy.



Rachna Pradhan

Rachna Pradhan contributed to team morale and competitive spirit.



Anil Kumar

Anil Kumar helped guide the team, enhancing team discipline and strategy.

विस्तृत जानकारी (RAS मुख्य परीक्षा हेतु):

- **प्रतियोगिता का महत्व:** राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता देश में बर्फीले खेलों के प्रचार हेतु एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है।
- **राजस्थान की भागीदारी:** रेगिस्तानी प्रदेश होने के बावजूद राजस्थान के 28 खिलाड़ियों ने अनुकरणीय तैयारी और खेल भावना का प्रदर्शन किया।
- **नेतृत्व की भूमिका:**
 - संजीव कुमार, रचना प्रधान व अनिल कुमार ने टीम का मार्गदर्शन किया, जिससे टीम में अनुशासन और रणनीति मजबूत रही।
- **राष्ट्रीय मान्यता:** आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुख्य सचिव द्वारा प्रशंसा से राज्य को खेल नीति में प्राथमिकता मिल सकती है।
- **गैर पारंपरिक खेलों को बढ़ावा:** यह सफलता राज्य में विविध खेलों को अपनाने की प्रवृत्ति को दर्शाती है।
- **भविष्य की संभावनाएं:**



- युवाओं को नए खेलों में अवसर प्राप्त होंगे।
- आर्टिफिशियल आइस रिंग या प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की संभावना।
- राज्य खेल नीति में शीतकालीन खेलों को सम्मिलित करने की दिशा में प्रयास।

MCQs

Subject: Sports

Topic: National Ice Skating Championship

Question: Who led the Rajasthan team in the 20th National Ice Skating Championship held in Dehradun?

- A) Jagraj Singh
- B) Anil Kumar, Rachna Pradhan, and Sanjeev Kumar
- C) Ramesh Rawat
- D) Rajeev Sharma

Answer: B

Explanation: The Rajasthan team was led by Sanjeev Kumar, Rachna Pradhan, and Anil Kumar during the event in Dehradun.

प्रश्न: देहरादून में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का नेतृत्व किसने किया?

- A) जगराज सिंह
- B) अनिल कुमार, रचना प्रधान एवं संजीव कुमार
- C) रमेश रावत
- D) राजीव शर्मा

उत्तर: B

व्याख्या: प्रतियोगिता के दौरान राजस्थान टीम का नेतृत्व संजीव कुमार, रचना प्रधान और अनिल कुमार ने किया।

Question: Which national-level figure praised the Rajasthan team's performance in the ice skating championship?

- A) Chief Minister of Rajasthan
- B) Secretary General of Ice Skating Association of India
- C) Sports Minister of India
- D) Olympic Committee Chairperson

Answer: B

Explanation: Jagraj Singh, Secretary General of the Ice Skating Association of India, praised the performance.

प्रश्न: आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान टीम के प्रदर्शन की सराहना किसने की?

- A) राजस्थान के मुख्यमंत्री
- B) आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुख्य सचिव
- C) भारत के खेल मंत्री
- D) ओलंपिक समिति के अध्यक्ष

उत्तर: B

व्याख्या: आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुख्य सचिव जगराज सिंह ने राजस्थान टीम के प्रदर्शन की सराहना की।



RASonly



<https://t.me/+9dLgyy8BipQ3YjB>



HYPERLINK
"https://rasonly.com" [htt](https://rasonly.com)
[ps://rasonly.com](https://rasonly.com)